

नई शिक्षा नीति ने डॉ. निशंक को दिलाई कामयाबी

□ डॉ. वीरेंद्र बर्वाल

'दृढ़ संकल्प के आगे तो दुनिया भी हारी है, निज लक्ष्य पाने हेतु मेरा संघर्ष जारी है।'

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की 2009 में लिखी कविता की उपरोक्त पंक्तियाँ उनकी राजनीतिक सफलता की मूल मानी जा सकती हैं। अध्यापक से विधायक, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और इसके बाद भारत सरकार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी तक पहुँचे डॉ. निशंक को उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम ने कामयाबी दिलायी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत कर न केवल सुखद और समृद्ध भारत की नींव रखने में अहम भूमिका निभायी, अपितु अन्य देशों का ध्यान भी भारत की ओर खींचा है। यह भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने कोविड काल में शिक्षण व्यवस्था को बेपटरी नहीं होने दिया और जेईई, नीट, नेट जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं को सुचारु संपन्न कराया।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्र में शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाले लगभग 19 महीने का समय हुआ है, लेकिन इस अवधि के हिसाब से उनके खाते में दर्ज उपलब्धियाँ कम नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सामने लाना उनकी बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। यह नीति भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। इस नीति में आत्मनिर्भरता है। यह जाँव ओरिएण्टेड, संस्कारयुक्त और मानव मूल्ययुक्त शिक्षा देगी, जिसकी आज भारत को नितान्त आवश्यकता है। हमें हमारी जड़ों को जोड़कर आसमान की ओर परवाज भरने वाली इस शिक्षा में बच्चों को लिखने-पढ़ने की स्वतंत्रता और भारतीय भाषाओं का संरक्षण किया गया है।

खास बात यह रही कि यह नीति एक-दो व्यक्तियों के विचार पर आधारित नहीं है। इसमें करोड़ों भारतीयों की अवधारणा, संकल्पना एवं विचार निहित हैं।

इसके निर्माण से पहले करोड़ों की संख्या में प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, विद्वानों और विशेषज्ञों के विचार और सुझाव लिए गए हैं। छात्रों पर से बस्ते का बोझ कम करने, युवाओं को रोजगार सर्जक बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने जैसी अनेक विशेषताओं से युक्त इस नीति की यह बड़ी खूबी कही जा सकती है कि इस में अभी तक नहीं के बराबर असहमति के सुर उठे हैं। अनेक सुझावों, परिचर्चाओं के साथ ही गहन अध्ययन, नफा-नुकसान के गंभीर विश्लेषण के बाद अस्तित्व में आयी इस शिक्षा नीति को लागू करना यद्यपि एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नीति के ढाँचे को देखकर इतना तय है कि यह देश की दिशा और दशा को बदलने में कामयाब रहेगी।

छह सालों से कागजों में कैद रही इस नीति को डॉ. निशंक सरकार के सामने लाने में कामयाब रहे। इसे अब लागू किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह नीति रस आयी। वे इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत जैसी अनेक संकल्पनाओं से बहुरंगी बनी इस नीति में भारतीयता का दर्शन समाहित है। यह नीति ज्ञान का ऐसा समावेश है, जिसमें विद्यार्थी नौकरी पैदा करने वाला बनेगा। बुनियादी से सीढ़ी-दर-सीढ़ी वह ज्ञान के विभिन्न सोपानों को पार करता हुआ शिखर पर पहुँचकर अपने विषय का एक्सपर्ट बन सकेगा। प्राचीन भारत की तरह अध्यापक की गरिमा की रक्षा होगी और उसे गुरु का वह सम्मान प्राप्त होगा, जिसके लिए भारतीय संस्कृति

की पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान रही है। भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पहल इसमें महत्वपूर्ण है। इससे हमारी प्रतिभा और पैसा दोनों भारत में ही रह पाएंगे।

यदि नीति में उल्लिखित यह बात लागू होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे और स्कूलों को पुस्तकों से समृद्ध किया जाएगा तो यह गाँवों को संवारने के लिए बड़ी बात हो सकती है। विद्यार्थियों को कम उम्र में 'सही को करने' का महत्व सिखाया जाना भी कम बड़ी बात नहीं है। सभी कार्यों में नैतिक आचरण अपनाने और सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों में बुनियादी मानवीय और सर्वधार्मिक मूल्य विकसित किए जाएंगे। उनमें त्याग, सहिष्णुता, निष्काम कर्म, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, समानता और बंधुत्व के गुण और भावनाएँ विकसित की जाएंगी। यदि हमारे युवा ऐसे सद्गुणों से युक्त हों तो भारत को प्रगति के पथ पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस नीति का लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा इसमें प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वंचित और हाशिये पर रह रहे समुदायों के बच्चों को उनका वाजिब हक मिलने से देश में समानता आना लाजिमी है।



इस नीति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से व्याप्त खामियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में व्यवस्था की जा रही है कि विनियमन, प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन), फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं द्वारा किए जाएंगे। एक ही छतरी के नीचे रहकर चार संस्थाएं या व्यवस्थाएं अपने कार्य करेंगी। इन चारों को भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के तहत स्थापित किया जाएगा।

इस नीति में विषय चयन के मामले में लचीलापन और स्वच्छंदता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सुधार की उम्मीद जगाती है। छात्रों को, विशेष रूप से माध्यमिक में अध्ययन के लिए लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प मिलेंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी सम्मिलित होंगे, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई और जीवन की योजनाओं के अपने मार्ग अपनाने के लिए स्वतंत्र हो सकें। वर्ष-दर-वर्ष बच्चों का सम्पूर्ण विकास और सिलेबस का व्यापक चुनाव माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की विशेषता होगी। माध्यमिक स्तर पर बच्चों को स्ट्रीम के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। 'कला', 'मानविकी' और 'विज्ञान' अथवा 'व्यावसायिक' या 'अकादमिक' जैसी कोई धारा नहीं रहेगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक कौशल जैसे विषय स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे।

बताया जाता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जिस शिद्दत के साथ इस नीति को अस्तित्व में लाया, उसी शिद्दत के साथ इसके क्रियान्वयन में जुटा हुआ है। पूरे देश ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व भी नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं। यह इस नीति की खूबी ही कही जा सकती है कि अनेक देश इसे अपने यहाँ लागू करने का मन बना रहे हैं।

कोविड काल में लगभग एक साल तक पूरी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना डॉ. निशंक की दूसरी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही इस काल में बच्चों की मानसिक समस्याओं के निराकरण में

भारत को और श्रेष्ठ बनाएगी यह नीति: निशंक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत को विश्व में सिरमौर बनाएगी, ऐसा विश्वास करते हुए डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं कि यह हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाओं का दस्तावेज है। यह नीति भारत को ज्ञान, समृद्धि, संस्कार, मानव मूल्यों के आधार पर विश्व में और श्रेष्ठता प्रदान करेगी। हम शिक्षा के मामले में भारत को पूरे विश्व के लिए एक दृष्टांत और प्रेरक बनाना चाहते हैं। हमने शिक्षा पर जीडीपी के व्यय का 6 प्रतिशत खर्च करने का निर्णय लिया है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। नीति पर अमल होने के बाद हमारी कला, संस्कृति, भाषाओं पर आया संकट दूर होगा, हमारे शिल्प को उसकी पहचान मिलेगी। हर हाथ में काम होगा। यह नीति भारत की अहम धरोहर साबित

होगी। इस नीति के निर्माण में भारत के करोड़ों बुद्धिजीवियों, विद्वानों, अध्यापकों आदि के विचार सामहित हैं। मुझे विश्वास है कि यह भारत का भविष्य बदलकर प्रगति के शिखर पर ले जाने में सफल रहेगी। शिक्षा जैसी पवित्र चीज को राजनीति से दूर रखने के हिमायती डॉ. निशंक कहते हैं कि हमने कोविड काल में शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित न होने देने का पूरा प्रयास किया है। हमारे लाखों अध्यापक और गैरशिक्षण कार्मिक व्यवस्था को संभालने में लगे रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के हमारे विद्यार्थियों ने अनेक उपयोगी आविष्कार और शोध इस दौरान किए।



'मनोदर्पण' जैसे कार्यक्रमों ने बच्चों की बड़ी सहायता की।

इस काल में कुछ लोग शिक्षा का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन डॉ. निशंक ने अपने चातुर्य से ऐसा नहीं होने दिया। वे नीट और जेईई परीक्षाओं को सियासत के जबड़े से किसी तरह खींचकर लाए। कोर्ट ने भी साथ दिया। परिणामस्वरूप, नीट और जेईई जैसी बड़ी परीक्षाएं निर्विघ्न संपन्न करा दी गयीं। स्वयं परीक्षाओं की कमान संभालना, अधिकारियों से समय-समय पर विमर्श

करना और दिशा-निर्देश देना, सोशल साइटों पर सक्रिय रहकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना, वेबिनारों के माध्यम से देश के नागरिकों को नई शिक्षा नीति की खूबियों से अवगत कराना, मीडिया के माध्यम से अपने फैसलों की जानकारी जनता तक पहुँचाना, अपने लोकसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से समन्वय, पार्टी आला नेताओं से संपर्क इत्यादि अनेक ऐसे कार्य हैं, जो डॉ. निशंक को इस मंत्रालय में अल्प समय में ही लोकप्रियता के ऊंचे पायदान पर ले गए।

